

## अनुच्छेद 101

### चर्चा में क्यों?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सांसद अमृतपाल सहि की याचिका पर सुनवाई स्थगति कर दी, जिसमें संसद में उपस्थिति होने की अनुमति मांगी गई थी।

### मुख्य बटु

- अनुपस्थितिपर कानूनी तर्क:
  - अमृतपाल सहि के वकील ने तर्क दया की याचिका दायर करने की तारीख से वह पहले ही 46 दिनों से अनुपस्थिति हैं।
  - [संवधान के अनुच्छेद 101\(4\)](#) के अनुसार, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थिति रहता है तो संसदीय सीट रक्ति घोषति की जा सकती है।
  - इस बात पर जोर दया गया कि इस सीमा तक पहुँचने में केवल छह दिन शेष हैं, जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- मामले की पृष्ठभूमि:
  - खडूर साहबि नरिवाचन क्षेत्र से सांसद अमृतपाल सहि ने पहली बार जनवरी 2025 में अदालत का रुख कया था।
  - उन्होंने अपने नरिवाचन क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिये संसद में उपस्थिति होने तथा केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की अनुमति मांगी।
  - उनकी याचिका में तर्क दया गया कि 19 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नरिवाचति सांसद के रूप में उन्हें अपने संसदीय कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

### अनुच्छेद 101(4)

- प्रमुख प्रावधान:
  - यदि कोई सांसद बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थिति रहता है तो उसकी सीट रक्ति घोषति की जा सकती है।
  - दिनों की गणना में वह अवधि शामिल नहीं है जब संसद सत्र में नहीं होती।
  - अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) अयोग्यता पर नरिणय लेते हैं।
- उद्देश्य:
  - वधायी कार्यवाही में सांसदों की सक्रयि भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - नरिवाचति प्रतिनिधियों द्वारा संसदीय ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा को रोकता है।
  - लोकतंत्र में जवाबदेही के सिद्धांत को कायम रखता है।
- अपवाद एवं विशेष मामले:
  - सांसद वैध कारणों, जैसे बीमारी, हरिसत में लयि जाने या अपरहार्य परिस्थितियों के कारण अवकाश के लयि आवेदन कर सकते हैं।
  - यदि सदन अनुमति दे देता है तो सांसद अपनी सीट बरकरार रख सकता है।
  - कानूनी हरिसत के मामलों में, यदि आवश्यक हो तो अदालतें उपस्थिति की अनुमति देने के लयि हस्तक्षेप कर सकती हैं।